नाबार्ड

अध्यक्ष की ओर से.....

हज़ार मील की यात्रा भी एक कदम से ही शुरू होती है.

लाओ सू

नाबार्ड की 40 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 आपके कर कमलों में प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हो रही है.

ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है, जब नाबार्ड ने 'भारत के विकास बैंक' के रूप में देश के ग्रामीण नागरिकवृन्द में समृद्धि लाने का महान कार्य करने के लिए अपने कदम रखे. वास्तव में जैसी कि समय की प्रवृत्ति होती है, तब से अब तक चार दशक तेज़ी से निकल गए – भारत के कृषि और ग्रामीण परिवेश को समर्थ, ऊर्जावान और सशक्त बनाने के 40 वर्ष. थोड़ा अतीत में चलते हैं, हमारी पहली वार्षिक रिपोर्ट 1982-83 ने, नाबार्ड के तुलन-पत्र का आकार ₹4,519 करोड़ का दिखाया था उस समय भारत का सकल घरेलू उत्पाद लगभग ₹ 1.97 लाख करोड़ था और उसका कुल खाद्यान्न उत्पादन करीब 128 मिलियन टन था. आज भारत का सकल घरेलू उत्पाद ₹ 236 लाख करोड़ से भी अधिक हो गया है, खाद्यान्नों का उत्पादन 314 मिलियन टन को छू गया और नाबार्ड का तुलन-पत्र ₹7.6 लाख करोड़ के बेहद प्रभावशाली आकार तक पहुंच गया !

अपने नाम के अनुरूप, नाबार्ड अपनी स्थापना से ही भारत के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित रहा. हमने हितधारकों के साथ सहयोग किया, बैंकिंग प्रणाली के साथ तालमेल बिठाया, विभिन्न सरकारी निकायों को अपने साथ लिया और अति कर्मठता से ऋण और सहकारिता (भारतीय

रिज़र्व बैंक के सहयोग से) के एक ग्रामीण परिवेश का निर्माण किया. हमने वित्तमान बढ़ाने के लिए असंख्य प्रयास किए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं, रियायती ऋण प्रदान करना, बुनियादी स्तर की संस्थाएं गठित करना (विकास वालंटियर वाहिनी, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, किसान-उत्पादक संगठन), कस्टमाइज़्ड वित्तीय उत्पादों (जैसे किसान क्रेडिट कार्ड) के डिज़ाइन तैयार करना, ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, वाटरशेडों का विकास और जनजातीय आजीविकाओं को संरक्षित करना और उनमें विविधता लाना.

अभी हाल ही में, नाबार्ड ने पिछले वर्ष की तुलना में 8.7% की अनुमानित वृद्धि के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था को महामारी के प्रभाव से बाहर निकालने में बड़ा योगदान दिया है. नाबार्ड ने महामारी के बाद के सबसे बुरे दौर में भी आशा की किरण जगाए रखने, विकास को बढ़ावा देने, और ग्रामीण भारत में समृद्धि लाने के लिए किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करना जारी रखा. वित्तीय वर्ष 2022 में हमारे तुलन-पत्र में 15.2% की वृद्धि हुई और बकाया ऋण 13.3% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹6.8 लाख करोड़ तक पहुंच गए. ₹3.6 लाख करोड़ के व्यावसायिक लक्ष्य के समक्ष, हमारी उपलब्धि ₹3.78 लाख करोड़ की रही; हमारा दीर्घावधि और अल्पावधि पुनर्वित्त 111% बढ़ गया और बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए मध्यम और दीर्घावधि निवेश ऋणों के समक्ष बकाया पुनर्वित्त 19.9% बढ़ गया जिससे आधार स्तर पर पूंजी निर्माण में तेज़ी आई.

हमने अपनी स्वयं की निधियों और साथ ही नोडल एजेंसी के रूप में हमारे पास रखी गई निधियों का उपयोग करते हुए भारत में ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करने के अपने मिशन को जारी रखा. ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत, ₹46,073 करोड़ की मंजूरी दी गई और इसके अंतर्गत दो नई गतिविधियां जोड़ी गईं यथा रेलवे क्रॉसिंगों पर रोड ओवर ब्रिजेस और रोपवेज़. इस प्रकार पात्र गतिविधियों की संख्या 39 हो गई. अब तक, ₹4.5 लाख करोड़ की संचयी राशि के साथ कुल 7.45 लाख परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई.

नीडा, सीएफएफ, डीआरए, डीआईडीएफ, एफ़आईडीएफ़, डब्ल्यूआईएफ इत्यादि जैसी हमारी विभिन्न निधियों के माध्यम से हमने सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आधारभूत संरचनाओं का संवर्धन किया है जैसे प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण के माध्यम से आवास, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के माध्यम से स्वच्छता. हमने खाद्य प्रसंस्करण आधारभूत संरचनाओं को सहायता प्रदान करने के क्षेत्र में विशेष रूप से अच्छा कार्य किया है और 16 राज्यों में 17 मेगा फूड पार्कों की परियोजनाओं, 8 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों और 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सहायता प्रदान की है.

एफएसपीएफ, पीओडीएफ, डब्ल्यूडीएफ, टीडीएफ, प्रोड्यूस, आदि जैसी निधियों का उपयोग करते हुए हमने पीपुल, प्लैनेट और प्रॉफिट (जनता, ग्रह और लाभ) रूपी अपनी 'ट्रिपल बॉटम एप्रोच' के साथ किसान समुदायों, कृषि नवोन्मेषों और प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए सहायता प्रदान की. मूल्य श्रृंखला, विपणन और बिक्री संबंधी आधारभूत संरचनाओं, हितधारकों के क्षमता निर्माण इत्यादि जैसी हमारी कृषीतर विकास पहलकदमियों ने सुफल देने शुरू कर दिए हैं और कृषीतर गतिविधियों की तरफ समुदायों का व्यवहारगत झुकाव स्पष्ट दिखाई देने लगा है.

कृषि पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड संधारणीय रणनीतियों और कृषि प्रबंधन को प्राथमिकता दे रहा है. 1990 के दशक की शुरुआत से ही नाबार्ड अपनी विभिन्न पहलों जैसे मिट्टी और जल संरक्षण परियोजनाओं, वाटरशेड, फार्म पॉण्ड, भू-जल रीचार्ज, नवीकरणीय ऊर्जा की परियोजनाओं, इत्यादि के माध्यम से संधारणीयता पर कार्य करता आ रहा है. मिट्टी और नमी संरक्षण एवं क्लाइमेट प्रूफिंग पर हमारी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं ने उच्चतर उत्पादकता और वैकल्पिक आजीविकाओं के माध्यम से समुदायों को बड़े पैमाने पर लाभान्वित किया है.

यूएनएफसीसीसी और एनएएफसीसी के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयनकर्ता संस्था के रूप में, ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए डायरेक्ट एक्सेस एंटिटी होने के अतिरिक्त नाबार्ड ने कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए अनेक उपायों की संकल्पना की, उनका निधीयन और संवर्धन किया. हमने ₹20 करोड़ की समूह निधि के साथ अपनी स्वयं की जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की ताकि हम ऐसे मार्ग खोज पाएं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल-जमीन-जंगल की उपलब्धता और उपयोगिता बढ़ा पाएं. जीवा नाम की एक नई पहल का भी शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य फसल प्रणालियों का विविधीकरण करना, पशुधन और वृक्षों को एक व्यवस्था के अंतर्गत लाना, जीव-विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को पुनरुज्जीवित करना और मिट्टी में नमी और वर्षा का दक्षता से प्रबंधन करना है.

अति भीषण महामारी के चलते लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था में शक्ति स्तम्भ के रूप में भारतीय कृषि की अद्भुत भूमिका का जश्न मनाते हुए हमने इस वर्ष के विषय-वस्तु अध्याय - धरती से सोना उगाती भारतीय कृषि को समर्पित किया है. मैं बार-बार यह दोहराते नहीं थकता कि अंत में, कृषि ही हमारे अस्तित्व के मूल में है, जो मानव के अस्तित्व को सुनिश्चित करती है और हमें आने वाली लड़ाइयों को लड़ने के लिए सहायता और शक्ति प्रदान करती है. महामारी ने मेरे इस विचार को सत्य साबित किया है. जब सब कुछ विफल हो जाता है, तब भी कृषि हमें उबारने के लिए डटी रहेगी, जब तक हम प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण और जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों की स्थिति में इसकी रक्षा और संरक्षा करते रहते हैं.

अपनी शानदार यात्रा के दौरान हमने जो भी उत्कृष्ट पहलें की हैं, उनमें से एक कार्य जिसने लाखों गरीब लोगों की ज़िंदगियों को पूरी तरह से बदल दिया, वह है हमारा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम (एसएचजीबीएलपी). वर्ष 1992 में 500 स्वयं सहायता समूहों को ऋण के साथ जोड़ने के मामूली लक्ष्य के साथ शुरुआत करने वाली इस अनूठी प्रायोगिक परियोजना ने कायांतरित होकर एक विशाल आंदोलन का रूप धारण कर लिया है जिसमें 1.18 करोड़ स्वयं सहायता समूहों को बचत से जोड़ा गया और 67.4 लाख को ऋण से जोड़ा गया. इसमें ₹47,240 करोड़ की जमाराशियां और ₹1.5 लाख करोड़ के बकाया

ऋण शामिल हैं. एक ओर जहां आंकड़े स्वयं ही आश्चर्यजनक हैं, वहीं दूसरी ओर लाखों की संख्या में हाशिए पर सिमट चुकी ग्रामीण महिलाओं को आवाज़, पहचान और आर्थिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना किसी क्रांति से कम नहीं है.

हमारे उल्लास में चार-चाँद लगाते हुए नाबार्ड की सहायक संस्थाएं, यानी हमारी सात सहयोगी संस्थाओं ने वर्ष के दौरान बेहतरीन कार्य किया और हमारे कार्यों को अपनी शानदार उपलब्धियों के साथ पूर्णता प्रदान की. मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में ये और अधिक ऊँचाइयाँ छुएंगी.

इस प्रतिष्ठित संस्थान के अध्यक्ष के रूप में, मैंने देश भर में व्यापक रूप से यात्रा की, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्य मंत्रियों, सांसदों से मिला और ब्यूरॉक्रसी के प्रतिष्ठित सदस्यों के साथ-साथ नागरिक समाज के साथ बैठकें कीं ताकि मौजूदा परिस्थितियों को समझ सकूं, ग्रामीण परिवेश की आवश्यकताओं का आकलन कर सकूं और नाबार्ड के सहयोगों के प्रभाव का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकूं. नाबार्ड की प्रासंगिकता और उसके योगदान के बारे में सभी के द्वारा साझा किए गए उत्साह, जोश और उमंग से मेरा दिल गर्व से भर जाता है.

आज मैं जब इस 40 वर्ष की यात्रा को याद करता हूँ तो आश्चर्यचकित रह जाता हूँ कि एक संगठन के रूप में हम कितने युवा हैं और काल के इस खंड में अपने प्यारे देश के लिए हमने कितने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं. ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपना पूरा करियर बिताने के बाद, यह तो मैं अधिकार के साथ कह सकता हूँ कि अपने पैमाने, मिशन, विज़न, भावना और आचार के धरातल पर एक विकासात्मक वित्तीय संस्था के रूप में नाबार्ड जैसी संस्था पूरे विश्व में दूसरी नहीं है.

जैसे-जैसे नाबार्ड अपने पांचवें दशक में प्रवेश कर रहा है, हम अपनी पुरानी यादों से अभिभूत हैं और यह हमारी वार्षिक रिपोर्ट में भी झलकता है. यह मेरे लिए और भी हृदयस्पर्शी हो जाता है क्योंकि मेरी व्यक्तिगत यात्रा भी नाबार्ड की स्थापना के साथ ही शुरू हुई, संगठन के साथ-साथ ही छोटे-छोटे कदम उठाए, आगे बढ़ा, समृद्ध हुआ, और शीर्ष पर पहुंच गया. मैं इस अवसर पर भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग जगत के अन्य सदस्यों, हमारे चैनल पार्टनरों और सबसे महत्वपूर्ण हमारे सम्मानित किसानों, जो नहीं होते तो हम भी नहीं होते, के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ.

धरती हमारी नहीं; हम धरती के हैं. साथ केवल यादें ले जाएं, छोड़ जाएं केवल अपने पदचिन्ह.

डॉ जी आर चिंतला

अध्यक्ष